इस व्यवस्था के अनुसार टिहरी बांध परियोजना का निष्पादन भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराई गई निधियों के माध्यम से और अंशतः पूर्तिकारों के ऋण के माध्यम से किया जाएगा ।

Dollar currency purchased by RBI

*411. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Reserve Bank of India has purchased dollar currency from the open market ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the details of such purchase made by the Reserve Bank of India during 1993-94;

(d) whether Government have taken any measures to stem the flood of dollars in the Indian market; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) Yes, Sir. The Reserve Bank of India has been purchasing US dollar from the Inter-Bank Market. Under Section 40 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Bank is required to quote its rates for spot purchase and sale of US dollars from/to authorised dealers in India. When the authorised dealers find the Bank's purchase rate attractive compared to the ongoing market rate or when there is no demand for US dollar in the inter-bank market they sell the US dollar currency to the RBI. Also, since the Reserve Bank of India is required to effect debt service payments on behalf of the Government of India and accounts for aid receipts as well, RBI purchases US dollars from the inter-bank market as and when there is a shortfall in aid flows compared to the debt service payments.

(c) The purchases made by the RBI during April, 1993 to March, 1994 amounted to US $ 13,855 million Month-wise details are as follows :—

	US $ (in million)
April 1993	820
May 1993	412
June 1993	619
July 1993	873
August 1993	786
September 1993	660
October 1993	862
November 1993	1007
December 1993	1839
January 1994	1189
February 1994	2929
March 1993	1859
Total	13855

(d) and (e) The strong improvements in the current account of the balance of payments in 1993-94 and the much higher flows of non-debt creating capital in the capital account have helped us build our foreign exchange reserves to comfortable levels.

उपग्रह मनीआर्डर प्रणाली

*412. **श्रीमती वीणा वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के कुछ चुनिंदा स्थानों पर, उन स्थानों को उपग्रह से जोड़कर माइक्रो अर्थ-स्टेशनों के माध्यम से मनीआर्डर भेजने की योजना शुरू कर रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि डाक विभाग विद्यमान प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मनीआर्डर को भेजने पर 1.86 रुपये की हानि उठाता है तथा उपग्रह प्रणाली से समय की बचत होगी तथा लागत भी कम आएगी; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें अब तक डाकघर नहीं हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैय्या नायडू) : (क) मनीआर्डर को एक डाकघर से दूसरे डाकघर को शीघ्र भेजने और साथ ही मनीआर्डर प्रचालन की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से विभाग ने 8 वीं योजना अवधि के दौरान देश में 75 स्थानों पर माइक्रो-अर्थ स्टेशन स्थापित करने का एक कार्यक्रम बनाया है । माइक्रो-अर्थ स्टेशन स्थापित करने के लिए 75 स्थानों की सूची विवरण दी गई है (नीचे देखिए)

विभाग ने पांच स्थानों, अर्थात् दिल्ली, मद्रास, बेंगलूर, लखनऊ और शिमला में पहले ही एक प्रायोगिक योजना शुरू कर दी है ।

(ख) उपग्रह मनीआर्डर के लिए टर्मिनल उपस्कर सहित, 75 माइक्रो-अर्थ स्टेशनों की स्थापना में 12 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है ।

(ग) यह हिसाब लगाया गया है कि मौजूदा प्रणाली में औसतन प्रति मनीआर्डर 1062 पैसे की कुल प्रचालन लागत की तुलना में मनीआर्डर से 876 पैसे की औसतन आय होती है तथा इस प्रकार प्रति मनीआर्डर 186 पैसे का घाटा होता है ।

परीक्षण के प्रस्तावित उपग्रह माध्यम में, मनीआर्डर प्रचालन लागत 1062 पैसे से घटकर 825.56 पैसे होने की संभावना है ।

(घ) मध्य प्रदेश में 66,404 ग्राम ऐसे हैं, जिनमें डाकघर नहीं हैं ।

विवरण

माइक्रो-अर्थ स्टेशनों (वी०एस०ए०टी०) के लिए स्थानों की सूची

क्र० सं०	सर्किल/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कस्बा/शहर/जिला मुख्यालय
1.	असम	1. गुवाहाटी
		2. सिल्चर
		3. तेजपुर
		4. डिब्रूगढ़
		5. उत्तर लखीमपुर
2.	आन्ध्र प्रदेश	1. हैदराबाद
		2. विजयवाड़ा
		3. विशाखापटनम
		4. तिरुपति
		5. कुर्नूल
3.	बिहार	1. पटना
		2. रांची
		3. गया
		4. पूर्णिया
		5. दरभंगा
		6. माधेपुरा
		7. मुजफ्फरपुर
4.	दिल्ली	
5.	गुजरात	1. राजकोट
		2. बड़ौदा
		3. अहमदाबाद
6.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला
		2. मंडी
7.	हरियाणा	1. अम्बाला
		2. रोहतक
8.	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू
		2. श्रीनगर
9.	कर्नाटक	1. बैंगलूर
		2. मैसूर
		3. धारवाड़
		4. मैंगलूर
		5. रायचूर
10.	केरल	1. त्रिवेन्द्रम
		2. कालीकट
		3. कोचीन
11.	मध्य प्रदेश	1. रायपुर
		2. जबलपुर
		3. इंदौर
		4. रतलाम
		5. भोपाल
		6. ग्वालियर
12.	महाराष्ट्र	1. नागपुर
		2. बम्बई
		3. पुणे
		4. पणजी
		5. औरंगाबाद
13.	उत्तर पूर्व	1. शिलांग
		2. एजवाल
		3. अगरतला
		4. कोहिमा
14.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर
		2. संबलपुर
15.	पंजाब	1. लुधियाना
		2. जलंधर
16.	राजस्थान	1. जयपुर
		2. जोधपुर
		3. उदयपूर
		4. अजमेर
		5. कोटा
17.	तमिलनाडु	1. मद्रास
		2. कोयम्बतूर
		3. मदुरै
		4. तिरुची
		5. थंजावूर

क्र० सं०	सैक्टिल/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कस्बा/शहर/जिला मुख्यालय
18.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ
		2. कानपुर
		3. वाराणसी
		4. आगरा
		5. इलाहाबाद
		6. सहारनपुर
		7. बरेली
		8. रुद्रप्रयाग
19.	पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता
		2. सिलीगुड़ी
		3. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (पोर्ट ब्लेयर)

बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्युत् उत्पादन की निजी/विदेशी परियोजनाएं

*413. **श्री दिग्विजय सिंह :**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी/विदेशी कंपनियों को बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्युत् उत्पादन की परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति देने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार इन राज्यों में विद्युत् की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत् मंत्री (श्री एन०के०पी०साल्वे) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने विष्णु प्रयाग जल विद्युत् परियोजना (400 मे०वा०), रोजा ताप विद्युत् केन्द्र (750 मे०वा०) और जवाहरपुर ताप विद्युत् केन्द्र (750 मे० वा०) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा बिहार सरकार ने चांबिल ताप विद्युत् केन्द्र (500 मे०वा०) को क्रियान्वयन के लिए निजी प्रवर्तकों को सौंप दिया है ।

Scam in the Bank of India

*414. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which was published in the Indian Express of March 18, 1994 revealing yet another financial scam in the Bank of India, wherein their high officials have duped the Bank of sixty crores of rupees; and

(b) if so, what are the details thereof and what stringent steps Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) On a complaint filed by Bank of India, CBI has registered a case on 22-2-94 against a former senior Vice President of Bank of India, New York branch and others for defrauding Bank of India to the extent of approximately Rs. 28.33 crores. The allegations in brief are that the former senior Vice President of Bank of India, in pursuance of a criminal conspiracy with certain borrowers in USA and some unknown officers of the bank and private parties, misused his official position and granted various credit facilities by exceeding his delegated authority and without making required credit assessment including pre-sanction inspection/post-sanction inspection. Further, the financial status of the borrowers was also not ascertained.

CBI have reported that in connection with this case, they have searched the residential premises of a former Chairman & Managing Director of Bank of India and seized certain assets and incriminating documents therefrom. Further action as warranted would be taken in accordance with the results of CBI investigation.

समाचारपत्रों, फिल्मों, दूरदर्शन इत्यादि पर अशोभनीय विज्ञापन और दृश्य

*415. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों, दूरदर्शन और फिल्मों में आने वाले अशोभनीय और अपमानजनक विज्ञापनों और दृश्यों के विरुद्ध कोई कदम उठाए हैं ;